Tripuri
A Multidisciplinary and Multilingual Double-Blind Peer-Reviewed International Research Journal
TRIPURI

नर्मदापुरम संभाग में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की पूंजीकरण प्रवृत्तियों का विश्लेषण

डॉ. अशोक कुमार राकेशिया[1], रोहित जैन[2]
[1]सह प्राध्यापक, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय पिपरिया, नर्मदापुरम
[2]शोधार्थी, शहीद भगत सिंह शासकीय स्नातकोत्तर, महाविद्यालय पिपरिया, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
मोब. नंबर- 9630143027
इमेल : jainrohit1093.rj@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.20485386

सारांश

यह शोध पत्र मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग (नर्मदापुरम, हरदा और बैतूल जिले) में कार्यरत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) की पूंजीकरण (Capitalization) प्रवृत्तियों और वित्तीय संरचना का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। किसी भी औद्योगिक इकाई की वृद्धि और विस्तार के लिए पूंजी का सही संयोजन—जिसमें स्वयं की पूंजी (Equity), बैंक ऋण (Debt), और सरकारी अनुदान शामिल हैं—अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि संभाग में पारंपरिक ऋण-आधारित पूंजीकरण का दबदबा है, जबकि उद्यम पूंजी (Venture Capital) और एंजेल निवेश जैसे आधुनिक स्रोत अभी भी नगण्य हैं।

कुंजी शब्द : पूंजीकरण प्रवृत्तियां, MSME, नर्मदापुरम संभाग, ऋण-समता संरचना, कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी।

1. प्रस्तावना

सुदृढ़ औद्योगिक ढांचे के बिना किसी भी क्षेत्र का सतत आर्थिक विकास संभव नहीं है। वर्ष 2027 तक 'विकसित भारत' (Viksit Bharat 2047) के निर्माण के व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करने में मध्य प्रदेश जैसे राज्यों के क्षेत्रीय औद्योगिक विकास-विशेषकर MSME क्षेत्र-की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। नर्मदापुरम संभाग अपनी मजबूत कृषि पृष्ठभूमि के कारण एग्रो-प्रोसेसिंग, लकड़ी आधारित और अन्य विनिर्माण

उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं रखता है।

पूंजीकरण (Capitalization) से तात्पर्य किसी उद्यम द्वारा अपने व्यवसाय को चलाने और विस्तार करने के लिए जुटाई गई कुल पूंजी से है, जिसमें ऋण और इक्विटी का अनुपात (Capital Structure) शामिल होता है। पर्याप्त और सही लागत वाली पूंजी की अनुपलब्धता MSMEs के विकास में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह शोध पत्र इस बात की पड़ताल करता है कि नर्मदापुरम संभाग के उद्यमी अपने व्यवसायों को पूंजीकृत करने के लिए किन स्रोतों पर निर्भर हैं और उनकी स्थिर (Fixed) तथा कार्यशील (Working) पूंजी की प्रवृत्तियां क्या हैं।

2. अध्ययन के उद्देश्य

1. नर्मदापुरम संभाग के MSMEs की पूंजी संरचना (स्वयं की पूंजी बनाम बाहरी ऋण) का विश्लेषण करना।
2. स्थिर पूंजी (मशीनरी, भूमि) और कार्यशील पूंजी (कच्चा माल, दैनिक खर्च) में निवेश की प्रवृत्तियों को समझना।
3. पूंजीकरण में सरकारी योजनाओं (जैसे PMEGP, मुद्रा योजना) और सब्सिडी के प्रभाव का मूल्यांकन करना।

3. शोध प्रविधि

- **अध्ययन का स्वरूप:** वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical)।
- **आंकड़ा संग्रहण:** प्राथमिक आंकड़े संभाग के 150 MSME संचालकों (प्रत्येक जिले से 50) के सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए। द्वितीयक आंकड़े राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC), जिला उद्योग केंद्रों (DIC), और MSME मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों से प्राप्त किए गए हैं।
- **विश्लेषण के उपकरण:** प्रतिशत विश्लेषण, औसत और ऋण-इक्विटी अनुपात का उपयोग किया गया है।

4. आंकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

4.1 पूंजीकरण के स्रोत

चयनित उद्यमों की कुल पूंजी में विभिन्न स्रोतों के योगदान का जिलावार औसत प्रतिशत नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

जिला	स्वयं की पूंजी (Promoter's Equity)	संस्थागत बैंक ऋण (Institutional Debt)	सरकारी अनुदान/सब्सिडी (Govt. Grants)	अनौपचारिक ऋण (Informal Debt)
नर्मदापुरम	35%	48%	12%	5%
हरदा	28%	45%	15%	12%
बैतूल	25%	42%	18%	15%

व्याख्या:

आंकड़े दर्शाते हैं कि संभाग में पूंजीकरण मुख्य रूप से बैंक ऋण पर निर्भर है। नर्मदापुरम जिले में स्वयं की पूंजी का अनुपात (35%) सबसे अधिक है, जो वहां के उद्यमियों की बेहतर वित्तीय क्षमता को इंगित करता है। वहीं, बैतूल और हरदा में सरकारी सब्सिडी पर निर्भरता अधिक है, लेकिन साथ ही साहूकारों या रिश्तेदारों से लिए गए अनौपचारिक ऋण (Informal Debt) का प्रतिशत भी वहां ज्यादा है, जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में आ रही बाधाओं को दर्शाता है।

4.2 स्थिर बनाम कार्यशील पूंजी की प्रवृत्तियां

- **स्थिर पूंजी (Fixed Capital):** पिछले पांच वर्षों में, एग्रो-प्रोसेसिंग और पैकेजिंग उद्योगों में आधुनिक मशीनरी की स्थापना के कारण स्थिर पूंजी में निवेश बढ़ा है।
- **कार्यशील पूंजी (Working Capital):** संभाग के लगभग 65% उद्यमों ने कार्यशील पूंजी की कमी को अपनी सबसे बड़ी समस्या बताया है। पूंजीकरण का एक बड़ा हिस्सा मशीनरी में लग जाने के कारण, दैनिक संचालन के लिए नकदी प्रवाह का प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है।

4.3 ‘ओवर-कैपिटलाइजेशन’ और ‘अंडर-कैपिटलाइजेशन’ की स्थिति

विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि हरदा और बैतूल के कई सूक्ष्म उद्यम 'अंडर-कैपिटलाइज्ड' (Under-capitalized) हैं, अर्थात उनके पास अपनी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं है। इसके विपरीत, नर्मदापुरम के कुछ मध्यम आकार के उद्यमों में मशीनों पर अत्यधिक व्यय के कारण 'ओवर-कैपिटलाइजेशन' के लक्षण दिखे हैं, जिससे निवेश पर प्रतिफल (Return on Investment) प्रभावित हुआ है।

5. निष्कर्ष

नर्मदापुरम संभाग में MSME पूंजीकरण की प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से पारंपरिक है, जहाँ इक्विटी (स्वयं के निवेश) के बजाय ऋण-आधारित वित्तपोषण (Debt-financing) को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि सरकारी योजनाओं के माध्यम से क्रेडिट गारंटी और सब्सिडी ने पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन संस्थागत वित्तीय पहुंच अभी भी सभी के लिए समान नहीं है। संभाग के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए पूंजी संरचना में विविधता लाना आवश्यक है।

6. सुझाव

1. **वैकल्पिक वित्तपोषण तंत्र:** उद्यमियों को केवल बैंक ऋण पर निर्भर रहने के बजाय एंजेल निवेशकों, क्राउडफंडिंग और वेंचर कैपिटल जैसे आधुनिक पूंजीकरण स्रोतों के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए।
2. **कार्यशील पूंजी ऋण सुगमता:** बैंकों को संपार्श्विक (Collateral) मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए CGTMSE (क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज) योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर जोर देना चाहिए।
3. **वित्तीय सलाहकार सेवाएं:** जिला उद्योग केंद्रों (DIC) के स्तर पर 'वित्तीय परामर्श सेल' स्थापित किए जाने चाहिए जो उद्यमियों को सही पूंजीकरण संरचना (Capital Structure) तय करने में मदद करें ताकि वे अंडर या ओवर-कैपिटलाइजेशन से बच सकें।

7. संदर्भ सूची

1. चौहान, पी., एवं राठौर, एम. (2023). मध्य प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की वित्तीय संरचना:

एक विश्लेषणात्मक अध्ययन. *इंडियन जर्नल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज, 14*(3), 45-58. https://doi.org/10.18843/ijcms/v14i3/05

2. भारतीय रिज़र्व बैंक. (2024). *सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ऋण प्रवाह पर वार्षिक रिपोर्ट.* https://www.rbi.org.in/
3. मध्य प्रदेश शासन. (2022). *मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास नीति और MSME परिदृश्य.* वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, भोपाल.
4. शर्मा, के. एल. (2023). *भारत में औद्योगिक अर्थशास्त्र एवं वित्तीय प्रबंधन.* साहित्य भवन पब्लिकेशन्स.
5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय. (2024). *MSME क्षेत्र के लिए क्रेडिट गारंटी योजना: प्रगति रिपोर्ट.* भारत सरकार. https://msme.gov.in/